India-based and local posts in our Missions in this important region. This will enable our Embassies to function more efficaciously in realizing the trade potential, and other possibilities for economic collaboration.

पर्वतीय क्षेत्रों में खनिजों के लिए सर्वेक्षण

8379. **श्री भारत भूषण :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पर्वतीय क्षेत्रों में छिपी हुई खनिज सम्पदा की खोज के लिए सर्वेक्षण करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) और (ख). देश के पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिए कोई अलग योजना नहीं है । लेकिन भूगर्भ सर्वेक्षण एक लगातार चलने वाला कार्य है ; तथा केन्द्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रैमिंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित भारतीय भू-सर्वेक्षण के वार्षिक खोज कार्यक्रम में देश के पर्वतीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी शामिल होता है । चालू क्षेत्रगत सत्र कार्यक्रम (अक्टूबर, 1977 से सितम्बर, 1978) में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश के पर्वतीय क्षेत्रों में, क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्रण के अलावा, बाक्साइट, कोयला, चूना-पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनेटाइट, ग्रेफाइट, सिलीमेनाइट, निकिल, कोवाल्ट, वर्मीकुलाइट, टगस्टन, आधार धातुओं जैसे खनिजों और खनिज-झरनों के लिए अनेक खोजें करने का प्रस्ताव है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

762 L. S.—4

Guide Lines for withdrawal of Prosecution cases of Provident Fund

8380. **SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI :** Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether any guid lines have been laid down for the withdrawal of prosecutions cases launched against defaulters of provident fund dues;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether many prosecution cases were withdrawn recently without bothering about these guide-lines ; and

(d) if so, the details of those cases and the reasons for not adhering to the guide-lines ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA) : The Provident Fund Authorities have reported as under : (a) and (b). Yes. The general guide-lines laid down by the Central Provident Fund Commissioner for the withdrawal of prosecution cases launched against defaulters of provident fund dues are :—

(i) the accused should be the offender for the first time and has not been convicted earlier for a similar offence; there should be no other prosecution pending against him;

(ii) the accused should set right all the contraventions for which the complaint was filed,

(iii) his current performance including in the matter of payment of all the dues is uptodate;

(iv) the accused has paid into the Fund the amount of damages due on the amount which remained outstanding for the entire period of default and also reimbursed the legal and other expenses incurred by the Regional Provident Fund Commissioners Offices in connection with the prosecution;

(v) where the employer has not paid the outstanding dues, he is required to offer a Bank guarantee from a Scheduled Bank for the total amount of dues, the probable amount of damages leviable and the legal and other expenses involved. He should also undertake to pay the current dues and the amount of instalments promptly and also to pay the amount if any due in respect of any outgoing member in one lumpsum;

(vi) Where an employer is not able to offer a Bank guarantee but produces collatoral securities for double the amount of dues outstanding and for the damages and legal expenses, he is required to give an undertaking to abide by the conditions relating to promptness in payment of current dues and instalments etc. as specified in the preceding item.

(c) and (d). All cases where the prosecution cases were withdrawn were examined in detail to ensure that these cases by and large fell within the guidelines enumerated above.

Condition of Indian Workers in Iran and other Arab countries

8382. SHRI RAM DHARI SHASTRI: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the press reports appearing in the 'Statesman' dated the 5th April, 1978 that Indian workers going to Iran and other Arab countries have been starving and there is no body to see to their interests;

(b) whether some bogus agencies are engaged in sending Indian labour abroad by offering them allurements and are extorting money from them in the name of bringing them prosperity; and

(c) if so, the names of such companies and remedial action being taken by Government ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) No case of starvation of Indian workers has come to the notice of the Government.

(b) and (c). As and when complaints about unauthorised recruitment are received, these are got investigated through appropriate authorities and suitable action taken in the light of the results of investigation.

मैसर्स ए० एच० ह्वीलर के रेलवे बुक स्टालों के एजेंटों द्वारा भूख हड़ताल

8383 . श्री रामानन्द तिवारी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ए० एच० ह्वीलर के रेलवे बुक स्टालों के एजेंटों ने शोषण और दमन के विरुद्ध रोष व्यक्त करने के लिए और अपनी सात सूत्री मांगों के समर्थन में 12 जनवरी, 1978 से भूख हड़ताल की थी और उनके द्वारा आश्वासन दिये जाने पर 21 जनवरी, 1978 को हड़ताल समाप्त की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उनको क्या आश्वासन दिये गये थे और उन आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख). रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, मैसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, जो रेलवे बुक स्टालों के ठेकेदार हैं, अपने बुक स्टालों की उन द्वारा नियुक्त बुकस्टाल एजेंटों द्वारा प्रबन्ध चलाते है । चार भूतपूर्व बुक स्टाल एजेंटों ने, जिन की एजेंसियां 4 से 10 वर्ष पहले धन के अभिकथित गबन के कारण समाप्त की गई थी, 13 जनवरी से 21 जनवरी, 1978 तक इलाहाबाद में अपने मुख्य कार्यालय के सामने आन्दोलन किया । यह बताया जाता है कि वे सभी उच्च न्यायालयों/निचली अदालतों में कानूनी मामले हार चुके हैं या उनके विरुद्ध न्यायालयों में मामले पड़े हुए हैं । राज्य श्रम मंत्री के कहने पर सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश ने एजेंटों की शिकायतों की विस्तार से जांच की और अन्त में यह आन्दोलन जनवरी 21, 1978 को वापस ले लिया गया ।

प्राइवेट दुकानों को बेची गई केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की दवायें

8384. श्री अजय सिंह ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जिन दवाओं पर 'केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य